

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

संक्षेप

अपर मुख्य सचिव/  
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग -1

देहरादून, दिनांक : 07 जनवरी, 2010

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय की स्वीकृतियाँ शासनादेश संख्या- 515/XXVII(1)/2009, दिनांक 28 जुलाई, 2009 द्वारा निर्गत की गयी थी। इसी क्रम में प्रथम अनुपूरक मांग एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम-2009 पारित होने के फलस्वरूप प्रथम अनुपूरक मांग की धनराशियाँ प्रशासनिक विभागों के निर्वहन पर इस आशय से रखी जा रही है कि -

2- प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित दलनरुद्ध मदों यथा 01-वेतन, 02-मजदूरी, 03-महंगाई भत्ता, 06-अन्य भत्ते, 09-विद्युत दाय, 10-जलकर/जलप्रभार, 13-टेलीफोन पर व्यय, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान, 17-किराया उपश्रुक्त और कर स्वामित्व, 21-छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन, 27-निकिरसा व्यय प्रतिपूर्ति, 48-महंगाई देतन एवं 49-महंगाई पेंशन आदि मदों की धनराशि वित्त विभाग की सहमति के बिना प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से व्यय हेतु स्वीकृत कर सकते हैं। आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की अन्य मदों में प्राविधानित धनराशि वित्त विभाग की सहमति के बिना स्वीकृत नहीं की जायेगी।

3- प्रथम अनुपूरक अनुदान में राज्य योजना एवं जिला योजनातर्गत की गई कजट व्यवस्था की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही दी जायेगी भले ही इसके लिये परिच्यय उपलब्ध हो।

कृपया उपर्युक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त

संख्या DS (1)/XXVII(1)/2010 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, डीबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, मजरा, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. शासन के समस्त अनुभाग।
4. एन० आई० सी०, सचिवालय, देहरादून।
5. उपनिदेशक शासकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश की 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. रामभक्त लाला हरिप्रसाद, कीर्षाधिकारी / कीर्षाधिकारी उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(जी० एन० सी० जी० सी०)

अपर सचिव, वित्त